भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 702

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।

02 श्रावण, 1948 (शक)

इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति

702. डा. कविता पाटीदारः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री बृज लालः
श्रीमती माया नारोलियाः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः
डा. दिनेश शर्माः
डा. संदीप कुमार पाठकः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मई 2026 तक इंडियाएआई मिशन के तहत भारत में एआई शासन संबंधी दिशानिर्देश के अनुसरण में शुरू की गई पहलों सहित हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत स्वदेशी एआई फाउंडेशन मॉडल, सामान्य कंप्यूट अवसंरचना और एआई डेटासेट के विकास की स्थिति क्या है;
(ग) उत्तर प्रदेश सहित देश के स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) एआई प्रौद्योगिकियों का उत्तरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** भारत की एआई नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य इससे जुड़े जोखिमों का समाधान करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार पैदा करना है।

भारत की एआई रणनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख मजबूत कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है। इंडिया एआई मिशन एआई मॉडल, एप्लिकेशन, डेटासेट, प्रतिभा विकास और वहनीय कम्पयूट के विकास सहित सात स्तंभों के तहत भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है।

इंडियाएआई मिशन के तहत अब तक की प्रगति:

एआई मॉडल:

भारत सरकार बड़े भाषा मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय स्टार्टअप और संस्थानों का समर्थन कर रही है।

समर्थन के लिए 20 स्वदेशी सॉवरेन मॉडल प्रस्तावों की पहचान की गई है, जिसमें 12 एलएलएम और 8 एसएलएम शामिल हैं। अब तक की उल्लेखनीय सफलताओं में शामिल हैं:

- सर्वम एआई का सर्वम 30 बिलियन पैरामीटर और 105 बिलियन पैरामीटर मॉडल
- ज्ञानी.आई का स्पीच-टू-स्पीच मॉडल
- भारतजेन के बहुभाषी फाउंडेशन मॉडल
- अवतार एआई का वीडियो जनरेशन मॉडल

डोमेन-विशिष्ट एसएलएम में स्वास्थ्य सेवा, भाषा प्रौद्योगिकियों और एजेंटिक एआई सिस्टम का समाधान करने वाले विशेष मॉडल और एआई फ्रेमवर्क शामिल हैं, जो विकास और तैनाती के विभिन्न चरणों में हैं।

वहनीय कम्पयूट:

- पैनलबद्ध कम्पयूट सेवा प्रदाता : 15
- समर्थित परियोजनाओं की संख्या: 237
- स्वीकृत जीपीयू घंटे: 93.18 लाख जीपीयू घंटे

अनुप्रयोग विकास:

- 12 राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन/इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किए गए
- 62 एआई प्रोटोटाइप और 20 एआई समाधान परिनियोजन के विकास का समर्थन किया

प्रतिभा विकास:

- 178 संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में 686 फेलोशिप प्रदान की गई हैं
- सभी के लिए युवा एआई कार्यक्रम को 26.5 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा पूरा किया गया है।

इंडियाएआई लैब्स:

- 27 इंडिया डेटा और एआई लैब्स स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने 2500 से अधिक छात्रों के लिए प्रशिक्षण का समर्थन किया है
- अतिरिक्त 188 प्रयोगशालाओं पर काम चल रहा है।

डेटासेट:

एआईकोष प्लेटफ़ॉर्म 329 एआई मॉडल, 35 टूलकिट और 202 प्रलेखित उपयोग के मामलों को होस्ट करता है।

एआई उत्कृष्टता केंद्र:

सरकार ने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उद्योग भागीदारों के सहयोग से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 58 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एआई-सीओई) की स्थापना के लिए एक योजना को भी मंजूरी दी है।

भारत एआई शासन दिशानिर्देश:

इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश 5 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे, जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास और नियोजन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करते हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, निम्नलिखित संस्थागत तंत्र शुरू किए गए हैं:

- एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप (एआईजीईजी), भारत की राष्ट्रीय एआई शासन रणनीति के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी निकाय है
- तकनीकी और नीतिगत सिफारिशों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी)
- सुरक्षा अनुसंधान करने, मानकों को विकसित करने, एआई सिस्टम का परीक्षण करने और उभरते जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए एआई सुरक्षा संस्थान (एआईएसआई)

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट:

इसके अलावा, भारत ने 16 से 21 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को होस्ट किया, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाली वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन श्रृंखला का पहला संस्करण है, जो भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार, शासन, साझेदारी और समावेशी विकास के

लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले एक ऐतिहासिक वैश्विक अभिसरण के रूप में संपन्न हुआ।

इंडियाएआई मिशन सूचीबद्ध क्लाउड सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सस्ती एआई कंप्यूट एक्सेस प्रदान करता है। जगह चाहे कोई भी हो, पूरे देश में इसकी सुविधा उपलब्ध है।

पात्र अंतिम उपयोगकर्ता उत्तर प्रदेश सहित भारत के किसी भी हिस्से से एआई कंप्यूट संसाधनों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इंडियाएआई मिशन के फ्यूचरस्किल्स स्तंभ के तहत, इंडियाएआई ने राज्य भर में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (जीआईटीआई) में इंडियाएआई डेटा लैब्स स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भागीदारी की है।

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (आईटी एंड ई) के तहत उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) और इंडियाएआई के बीच 26 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया।

इसका उद्देश्य एआई-आधारित समाधानों को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एनएसक्यूएफ-संरेखित अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 10वीं, 12वीं और आईटीआई डिप्लोमा छात्रों को मूलभूत और अनुप्रयुक्त एआई/डेटा विज्ञान कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित डेटा और एआई लैब स्थापित करना है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में एआई शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 64 डेटा और एआई लैब को मंजूरी दी गई है। इसमें गोरखपुर और लखनऊ में एनआईईएलआईटी केंद्रों में 2 विशेष प्रयोगशालाओं के साथ-साथ दो चरणों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में स्थापित 62 डेटा और एआई लैब शामिल हैं।

इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य डेटा विज्ञान, एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे एआई कौशल तक पहुंच का विस्तार हो और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के विकास का समर्थन किया जा सके। उत्तर प्रदेश के 5 छात्रों को इंडियाएआई फेलोशिप भी मिली है।

इंडियाएआई उत्तर प्रदेश में 03 एआई उत्कृष्टता केन्दों (सीओई) की स्थापना का भी समर्थन कर रहा है। एंकर संस्थान एकेटीयू लखनऊ, एचबीटीयू कानपुर और आईआईआईटी लखनऊ हैं।

केंद्र स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, शहरी प्रबंधन और आपदा लचीलापन सहित प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ सार्वजनिक सुरक्षा, संरक्षा और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए अनुप्रयुक्त एआई अनुसंधान, नवाचार और नियोजन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

(घ) सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने से जुड़े जोखिमों से अवगत है और उसने सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी एआई नियोजन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

- इंडियाएआई मिशन के 'सुरक्षित और विश्वसनीय एआई' स्तंभ के तहत, 13 जिम्मेदार एआई परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें पूर्वाग्रह शमन, व्याख्यात्मकता, गोपनीयता-संरक्षण एआई, एल्गोरिदम ऑडिटिंग, डीपफेक डिटेक्शन, एआई फोरेंसिक, जोखिम मूल्यांकन और जनरेटिव एआई सुरक्षा शामिल है, जिसमें साक्ष्य नामक डीपफेक डिटेक्शन के लिए एक मल्टी-एजेंट फ्रेमवर्क और एआई विश्लेषक नामक एक ऑडियो-विजुअल जालसाजी का पता लगाने वाला सिस्टम शामिल है।

- इंडियाएआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना एआई सुरक्षा, संरक्षा और विविध हितधारकों के साथ विश्वास विकसित करने, हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से शिक्षाविदों, स्टार्टअप, उद्योग और सरकारी निकायों को शामिल करने के लिए की गई है।

- इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश एल्गोरिथम पूर्वाग्रह, गलत सूचना, डीपफेक और अनपेक्षित सामाजिक नुकसान का समाधान करने के लिए एक जोखिम-आधारित शासन ढांचा निर्धारित करते हैं, और निरीक्षण, मानकों और सुरक्षा अनुसंधान के लिए एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप (एआईजीईजी), प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी) और एआई सुरक्षा संस्थान (एआईएसआई) सहित संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव करते हैं।

- डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 एआई अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

- भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) ने सितंबर 2024 में एसआईएसए के साथ सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सीएसपीएआई) कार्यक्रम शुरू करने के अलावा, प्रतिकूल एआई सम्बन्धी खतरों के खिलाफ सुरक्षा उपायों (मई 2023) और जनरेटिव एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों (मार्च 2025) पर परामर्शी निदेश जारी किए ।

*****